विजय रामलीला कमेटी का अवैध...

पेज 1 का शेष

की ओर से विजय रामलीला कमेटी की अवैध बिल्डिंग को तीन बार गिराने की कोशिश की गई लेकिन हर बार इसमें बाधा आई। सूत्रों का कहना है कि एमसीएफ की ओर से विवेक गिल इस इलाके के ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हैं। उनकी ड्यूटी दो बार इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए लगाई गई लेकिन विवेक गिल अपनी ड्यूटी से भाग खड़ा हुआ। उसने किनारा कर लिया। इसी तरह एक बार एमसीएफ को पुलिस ही नहीं मिली कि वह मौके पर जाती। इस तरह एमसीएफ के तीन बार के प्रयास बेकार चले गए। सूत्रों का कहना है कि धार्मिक मामला होने की वजह से एमसीएफ के अफसर पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। इसलिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हर बार गायब हो जाता है।

भगवान के अलावा नेताओं का आसरा

विजय रामलीला कमेटी के चेयरमैन सुनील कपूर जो पेशे से कबाड़ का धंधा करते हैं, ने बताया कि विधायक सीमा त्रिखा, मंत्री कृष्णपाल गूर्जर हमारी बिल्डिंग को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमें उन्हीं से उम्मीदें हैं। लेकिन हमारी मुख्य उम्मीद भगवान राम से है। सुनील कपूर ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर वर्षों पहले विजय रामलीला कमेटी के प्रबंधन ने कागज बनवाने पर ध्यान दिया होता तो आज संकट के दिन नहीं देखने पड़ते। सुनील कपूर ने भावुक होकर कहा कि इस संकट की वजह से हमारी रातों की नींद गायब है। बजरंगबली और भगवान राम से दिनरात विनती कर रहे हैं। चेयरमैन कपूर ने बताया कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने दस दिन पहले एमसीएफ कमिश्नर और जिला उपायुक्त यशपाल यादव से मुलाकात कर इस बिल्डिंग को बचाने के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने भरोसा दिया है कि वो इस मामले की फाइल निकलवाकर पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल एमसीएफ कमिश्नर के मौखिक निर्देश पर इस बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई रुकी हुई है लेकिन रामलीला कमेटी की बिल्डिंग न गिराने की स्थिति में अदालत में एमसीएफ की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा, यह कमिश्नर यशपाल यादव के अलावा और कोई नहीं जानता।

बता दें कि विजय रामलीला कमेटी पिछले साल उस समय विवाद में आई थी जब शहर के पूर्व मेयर अशोक अरोड़ा के पुत्र भारत अरोड़ा और कमेटी के पदाधिकारियों के बीच मारपीट हुई थी। मामला पुलिस तक भी पहुंचा था।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. राम खिलावन-बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने 9891164794
6. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
7. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421

कोरोनाकाल में भी ईएसआईसी अस्पताल ने दिखाया दम

फ़रीदाबाद (म.मो.) एनएच-3 स्थित ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यूं तो कोरोना मरीज़ चार अप्रैल 2020 से ही आने शुरू हो गये थे। लेकिन उस वक्त यह अस्पताल केवल बीमाकृत मज़दूरों के लिये ही उपलब्ध था। महामारी का प्रकोप बढने लगा और सरकार के पास उससे निपटने का कोई प्रबन्ध नहीं था तो 25 अप्रैल को ईएसआईसी के इस अस्पताल को केन्द्र सरकार द्वारा कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया। इस सारे संक्रमण-काल में यहां कुल 4261 मरीज़ भर्ती हुए जिनमें से 325 की मौत हुई, 3934 ठीक होकर घर चले गये। शेष बचे हुए भी स्वस्थ होकर घरों को लौट गए हैं। मरने वालों में 265 मरीज ऐसे थे जिन्हें व्यापारिक अस्पतालों से वैंटिलेटर पर रेफर किये गये थे।

इस सराहनीय काम के पीछे यहां के 330 डॉक्टर और अन्य स्टाफ़ संक्रमित हुआ। इसमें से 50 लोग दो बार और 20 लोग तीन बार संक्रमित हुए।

इस अस्पताल की कार्यकुशलता एवं मरीज़ों के प्रति समर्पण की भावना को देखते हुए कानपुर तक के मरीज़ भी यहां इलाज कराने आये जो सरकारी खर्च पर किसी भी महंगे से महंगे व्यापारिक अस्पताल में अपना इलाज करा सकते थे। और तो और देश के श्रम मंत्री संतोष गंगवार भी अपने संक्रमित परिजनों को इलाज के लिये इसी अस्पताल में लेकर आये थे। वह बात अलग है कि मंत्री होने के नाते यहां हर तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला, यह तो उन्हें सभी अस्पतालों में मिल सकता था।

जानने योग्य बात यह है कि सरकारी सा दिखने वाला यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल चलाया जरूर सरकार का जाता है, परन्तु इसमें किसी सरकार के एक पैसे का भी योगदान नहीं है। औद्योगिक मज़दूरों के वेतन से साढे छः प्रतिशत (जो अब साढे चार प्रतिशत हो गया है) मासिक काट कर एकत्र धन से पूरा ईएसआईसी का सिस्टम चलता है। इसी पैसे से मंत्री समेत तमाम अफ़सरों का वेतन भी दिया जाता है। इस अस्पताल को 'कोविड' घोषित करने के बाद उन तमाम मज़दूरों को चिकित्सा सेवाओं से वंचित कर दिया गया था जिनके पैसे से यह अस्पताल बना व चलाया जा रहा है।

गौरतलब एक बात यह भी है कि व्यापारिक असपताल में लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद जब मरीज़ मरने को होता था तो उसे एम्बुलेंस में डाल कर ईएसआई के इस अस्पताल में भेज दिया जाता था। यहां मरने वाले अधिकांश मरीज़ ऐसे ही थे।

अस्पताल द्वारा दी गयी इस बेहतरीन सेवा के पीछे उन तमाम डॉक्टरों व स्टाफ़ खास कर सफ़ाई स्टाफ़ की विशेष भूमिका रही है। सरकार ने बेशक जरूरी स्टाफ़ की भर्ती न करके बड़ी संख्या में पदों को खाली रखा हुआ है, स्थाई की जगह ठेकेदारी में कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उसके बावजूद सबने अपना बेहतरीन योगदान दिया। अपनी इस सेवा के बदले अनेकों डॉक्टर व स्टाफ़ के लोग भी संक्रमित हुए, इन्टर्नशिप करने वाले नवोदित युवा डॉक्टरों ने एक साल काम का अनुभव प्राप्त करने की बजाय कोविड मरीज़ों पर ही अपना सारा समय लगा दिया। समाज को उनकी इस कुर्बानी का संज्ञान लेना चाहिये।

उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक ज़िले में 46282लोग कोरोना संक्रमित बताये गये हैं। इनमें से कुल 414 लोग़ों की मृत्यु हुई। मरने वाले अधिकांश मरीज़ बड़े महंगे व्यापारिक अस्पतालों से थे; इन अस्पतालों में से कोई भी अपने आंकड़े देने को तैयार नहीं। इससे भी आश्चर्यजनक एवं घोटाले की बू दे रहे हैं नगर निगम के आंकड़े, जहां सरकारी आंकड़े कोरोना मौतों की संख्या 414 बता रहे हैं वहीं नगर निगम ने 680 कोरोना मृतकों के अन्तिम संस्कार पर 10000 रुपये प्रति मृतक के हिसाब से 68 लाख खर्च कर दिये। जबकि क्रिया कर्म का सारा सामान लकड़ी आदि का खर्च मृतकों के परिजनों से कराया गया। लेकिन यह सब जांच का विषय है।

होटल मिलेनियम को शुरू से ही...

पेज एक का शेष

पुलिस की सेवा-पानी के बदले। परन्तु इस होटल में यह सब कुछ खुले आम होता आ रहा है। 'मज़दूर मोर्चा' की निगाह इस होटल पर शुरू से ही है, इसमें दो बार कमरा किराये पर लेकर दो रात गुजारने के बावजूद कुछ भी पुख्ता हासिल नहीं किया जा सका। इसके कर्मचारियों से दोस्ती गांठ कर फुटेज बनाने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा था बाबू क्या करोगे, यहां तो खुद बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी ऐय्याशी करने आते हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बड़े अधिकारियों के नाम तो वे नहीं बता सके परन्तु एक दिन चुपके से पूर्व सीपी संजय कुमार को प्रवेश करते हुए जरूर दिखा दिया। बहुत डरते-घबराते हुए नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर उसने बताया कि ये साहब तो अक्सर यहां आते रहते हैं।

होटल एक सार्वजनिक जगह होती है, वहां किसी भी अफ़सर का आना-जाना कोई गुनाह नहीं बनता और किसी पुख्ता सबूत के बिना 'मज़दूर मोर्चा' इस होटल पर रिपोर्टिंग करने से बचता रहा। हां, पिछले दिनों जब पूर्व सीपी संजय कुमार पर रिपोर्टिंग की गयी थी तो उसमें जरूर इस होटल मालिक मक्कड़ का नाम आया था जिसमें कहा गया था कि पूर्व सीपी का अरावली में एक बड़ा प्लॉट मक्कड़ के नाम पर है। इसके अलावा पलवल में बतौर एसपी अपनी तैनाती के दौरान, उस इलाके में एक होटल स्थापित कराने में काफ़ी मदद की थी। इसी तरह कई अन्य पुलिस अफ़सरों के साथ अपने 'रसूख' के बूते मक्कड़ बेधड़क होकर थाने के सामने अपना काला कारोबार खुले आम चला रहा है।

पत्रकार शिखा द्वारा किये गये उक्त प्रयास को लेकर खुद पत्रकारों में ही तरह-तरह की बातें, उनके उद्देश्य को लेकर की जा रही हैं। उन सब बातों को छोड़ कर इतना श्रेय तो शिखा को देना बनता ही है कि उसने बड़े काले धंधेबाज़ को ललकारते हुए सरेआम नंगा कर दिया है। इसके लिये वे बधाई की पात्र हैं।

गतांक की चीर-फ़ाड़

किसान आन्दोलन को बदनाम कर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

26 जनवरी को दिल्ली में जहां मोदी सरकार द्वारा राजपथ पर शासकीय परेड आयोजित की गई वहीं आउटर रिंग रोड पर किसानों की जत्थेबंदियों ने कुछ अपवाद को छोड़कर अनुशासित ढंग से ट्रैक्टर परेड निकाली। जिसको नज़रअंदाज़ कर साजिश के तहत हिंसात्मक घटनाओं पर फ़ोकस कर किसान आन्दोलन को बदनाम कर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। 'राष्ट्रीय राजधानी में गण बनाम तंत्र के सबक' में किसान ट्रैक्टर परेड व किसान आन्दोलन का सटीक विश्लेषण किया गया है।

मज़दूर मोर्चा के 31 जनवरी-6 फ़रवरी के अंक में समसामयिक ज्वलंत मुद्दों के विभिन्न पक्षों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे अनुशासित व शांतिपूर्ण देशव्यापी किसान आन्दोलन को आरएसएस, भाजपा, मोदी सरकार व भाजपा के आईटी सैल ने सीएए के विरुद्ध शाहीन बाग आन्दोलन की तरह खालिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी, टुकड़े-टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सली, देशद्रोही व विपक्ष विशेषकर कांग्रेस द्वारा बहकाए गए करार देकर उन्हें बदनाम करके फूट डालकर समाप्त करने के अनेक हथकंडे अपनाए। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान सरकार, प्रशासन तंत्र व पुलिस द्वारा एक षडयंत्र के तहत दो महीने से चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने की साजिश की, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत का रोते हुए का वीडियो सामने आने से नाकाम हो गई।

ट्यूनीशिया की चिंगारी से उपजे अरब स्प्रिंग मूवमैंट की तरह टिकैत के आंसुओं से उपजी प्रतिक्रिया के फ़लस्वरूप किसानों का रैला धरना-स्थलों पर पहुंचने लगा और आन्दोलन में नई जान आ गई तथा विभिन्न राज्यों में जगह-जगह पर किसान पंचायतों व महापंचायतों का दौर चल पड़ा।

'किसान आन्दोलन कुचलने के लिये सरकार का नंगा नाच हुआ नाकाम- हरियाणा और यूपी में किसान आधी रात धरना देने निकल पड़े', 'हरियाणा में बीजेपी-जेजेपी नेताओं का गांवों में हुक्का-पानी बंद, लौटने लगे ट्रैक्टर, पंचायतें हुई सक्रिय', राकेश टिकैत के आंसू और ट्यूनीशिया की चिंगारी' तथा एक-एक आंसू का बदला लेंगे।-रै म्हारा बूढा रूवा दिया तो के रही म्हारी जवानी।' में सरकार व प्रशासन तंत्र द्वारा दमनचक्र चला कर किसान आन्दोन को समाप्त करने की साजिश का पर्दाफ़ाश किया गया है।

दरअसल दीप सिद्धू और पन्नू गुट पहले से ही सरकार से मिले हुए थे। एक षडयंत्र के तहत इन गुटों के लिए करीब 18 किलोमीटर लंबा रास्ता साफ़ किया गया था तथा इन दोनों गुटों ने साजिश के तहत लाल किले की प्राचीर पर लगे एक खाली पोल पर धार्मिक झंडा फ़हराया था। ध्यान रहे कि दीप सिद्ध गुरदासपुर से भाजपा सांसद सन्नी दयोल का दाहिना हाथ रहा है और वह लोक सभा चुनाव में सन्नी का इलैक्शन एजेंट था तथा प्रधानमंत्री मोदी व गृहमंत्री अमित शाह के साथ फ़ोटो में दिखाई दे रहा है।

दिल्ली के साथ-साथ देश के 20 राज्यों से भी अधिक राज्यों में विभिन्न स्थानों पर किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन और ट्रैक्टर रैली की जो शांति पूर्ण और अनुशासित थे। वास्तव में किसान की लड़ाई राजनीतिक व्यवस्था से है न कि कानून व्यवस्था से। वह दो महीने से शान्तिपूर्वक दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठा हुआ है जहां से किसी भी अहिंसक घटना घटित होने की रिपोर्टिंग नहीं है।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने ट्रैक्टर परेड और उस दौरान हुई हिंसा की रिपोर्टिंग करने को लेकर वरिष्ठ संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने की कार्यवाही की निंदा करते हुए बयान जारी कर मांग की कि ऐसे मामले तुरंत वापिस हो और मीडिया को बिना किसी डर के आजादी के साथ रिपोर्टिंग करने की इजाजत दी जाए। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीकन दुजारिक ने बयान जारी कर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक सार्वभौमिक स्वतंत्रता है और लोगों को अपने मन की बात कहने और खुल कर बोलने में सक्षम होना चाहिये।

दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड और उस दौरान वहां हुई हिंसा की रिपोर्टिंग को लेकर वरिष्ठ नेताओं, संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह, हिंसा भड़काने, अशांति फ़ैलाने तथा आई टी एक्ट की धाराओं के तहत यूपी की योगी सरकार की नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसका 'योगी की गुंडई...कई पत्रकारों पर केस दर्ज-यूपी के हालात संभाले नहीं जा रहे, सरकार बौखलाई' में खुलासा किया गया है। ध्यान रहे कि यूपी समेत पांच राज्यों में इन सबके खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है। सिंघु बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग करने पर पुलिस ने स्वतंत्र पत्रकार मनजीत पूनिया को गिरफ़्तार किया है।